>

Title: Regarding issue of grant of special status to Bihar.

-

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): माननीय सभापति महोदय, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए बहुत दिनों से चर्चा चल रही है। रघुराज रामन कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। बिहार पिछड़ रहा है। जब झारखंड राज्य बना था तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पैकेज दिया था, उससे कुछ तरक्की बिहार में हुई थी। आज भी बिहार में आईआईटी, आईआईएम नहीं है। एम्स अस्पताल चालू नहीं हुआ है। नेशनल लॉ कॉलेज नहीं है। नालंदा यूनिवर्सिटी बनी तो है लेकिन आज तक पूरी तरह बन नहीं पाई है। विक्रमशिला का कोई विकास नहीं हुआ है, कोई चर्चा नहीं हुई है। चंपापुरी, भागलपुर में है, जैन समाज को तो माइनोरिटी में ले आए लेकिन उसका भी कोई विकास नहीं हुआ है। हमारा स्पष्ट मत है और बिहार सरकार भी कह रही थी कि केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा दे रही है। आज विशेष राज्य के नाम पर बिहार ठगा गया है। केंद्र सरकार के मंत्री जाकर बिहार में बयान देते थे, अखबारों में छपता था, लड्डू बंट गए, कहा गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल रहा है। बिहार की जनता के साथ छल हुआ है। बिहार की जनता के साथ धोखा हुआ है।

मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बिहार को पुरानी लंबित योजना का सारा पैसा देना चाहिए, एनएच में पैसा देना चाहिए। बिहार के साथ अन्याय हुआ है। दस करोड़ बिहार के लोगों को इस देश के विकास में अधिकार मिलना चाहिए। इस सरकार को यह करना चाहिए। यह जाती हुई सरकार है। अगर यह सरकार नहीं करेगी तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग बिहार को विशेष पैकेज दिलाएंगे। बिहार को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे।...(व्यवधान) यह सरकार सिर्फ धोखा दे रही है। बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ने बिहार के साथ छल किया है। या तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने न्याय किया था या हमारी सरकार बनेगी तो हम न्याय करेंगे। बिहार के साथ धोखा बंद करें। केंद्र सरकार एलान करे कि आज बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे। कृषि का विकास नहीं हुआ, नालंदा का विकास नहीं हुआ, उद्योग का विकास नहीं हुआ, विक्रमशिला का विकास नहीं हुआ। बिहार की जनता आज कराह रही है। बिहार की जनता इस सरकार से उम्मीद कर रही है।

आप तेलंगाना राज्य का निर्माण कर रहे हैं लेकिन बिहार के दस करोड़ लोगों को इस देश के संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं है। यह अधिकार बिहार के लोगों को भी है, बिहार भी इस देश का भाग है। बिहार के साथ जो अन्याय होगा उसे बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।

MR. CHAIRMAN :

Shri Jitendra Singh and

Shri Arjun Ram Meghwal are allowed to associate with the issue raised by Shri Syed Shahnawaz Hussain.

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (मुंगेर): इसी विषय पर नोटिस है।

MR. CHAIRMAN: Hon. member please continue your speech. He will be given time to speak.

श्री शरद यादव (मधेपुरा): माननीय सभापति जी, 2012 के बजट भाषण में यह स्पष्ट किया गया कि जो पिछड़े राज्य हैं, उनके लिए विशेष इंतजाम होना चाहिए। रघुराज रामन कमेटी का गठन हुआ। सितंबर, 2013 में समिति की स्थायी रिपोर्ट वित्त मंत्री जी को दी गई। योजना आयोग ने जो प्रदेश पिछड़े हैं, उनको घोषित करने की स्वीकृति दी। इसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और राजस्थान है। रिपोर्ट के क्रियान्वयन ने योजना आयोग ने सहमति दी लेकिन अचानक 22 नवंबर 2013 को वित्त मंत्रालय में निर्णय के लिए होन वाली बैठक को स्थगित कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने भी पिछड़े राज्यों की रिपोर्ट पर सहमति दी। डेढ़ करोड़ लोगों ने दस्तखत करके महामहिम राष्ट्रपति को दिए, माननीय प्रधानमंत्री से मिले। दिल्ली में बहुत बड़ी रैली बिहार के लोगों ने की, पटना में की, हर जिले में की। ये पिछड़े राज्य आज से नहीं हैं। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल में आई थी। इसमें बंगाल प्रेजीडेंसी के लोग हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश का बार्डर 700 किलोमीटर है। हिमालय की नदियां इनके सिर से आती हैं जिसके कारण हर साल तबाही होती है, जलजला आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछड़े राज्यों के लिए यह समिति स्थगित क्यों की गई? आप नए-नए तरीके, नए-नए पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। जो असली सवाल है, जिसके लिए आपने कमेटी बनाई, प्लानिंग कमीशन ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने स्वीकृति दी तो फिर वित्त मंत्रालय में जो मीटिंग होनी थी वह स्थगित क्यों हुई? मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि पिछड़े राज्यों का यह हक है। आपने पिछड़े राज्यों के लिए काफी दूर तक काम किया और काम करने के बाद अपने आप स्थगित कर दिया। अगर देश को बनाना है तो पिछड़े राज्यों को आगे करना होगा। मैंने आपको क्रमबद्ध बताया है।

इसके बारे में वित्त मंत्रालय को तत्काल सफाई देनी चाहिए और बताना चाहिए। पिछले बजट सेशन में उन्होंने अच्छा बोला था। वे पिछड़े राज्यों को लेकर आगे बढ़े थे, उनको आकर इस पर सफाई देनी चाहिए। मेरी आपसे यही विनती है।

MR. CHAIRMAN:

Shri Kalikesh Narayan Singh Deo and

Shri Shailendra Kumar are allowed to associate with the issue raised by Shri Sharad Yadav.

श्री शैलेन्द्र कुमार : सर, हम इस मुद्दे से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Those who want to associate, please send slips at the Table of the House.

...(*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I am only responding to the issues raised relating to the Raghuram Rajan Committee Report. I will make a very brief response to that. You will recall that the Raghuram Rajan Committee was appointed pursuant to my Budget Speech of last year. It was our Government's decision to appoint such a Committee to identity States which are far from the average of India. States on several parameters are far away from the average of India. Therefore, we said that we should identify those States and work-out a mechanism by which those States can be helped. Let me make it clear that Report and the reason for constituting that Committee had no reference to any particular State. ...(*Interruptions*) Therefore, a number of States are removed from the average. Therefore, we wanted to identify which those States are and find out a mechanism by which those States can be helped. The Raghuram Rajan Committee had a wide representation. They identified some parameters, using which, the States can be identified and they rank the States. Based on that rank, we have circulated that Report to all concerned. The Report is at the active consideration.

The second part of the Report says that a part of the Finance commission recommendations, which is a Constitutional body, apart from the Planning Commission devolution of funds, there are other funds and the devolution of those funds, the distribution of those funds, could be done under the pattern or under the norms suggestions by the Raghuram Rajan Committee. Those norms have also been circulated to all the Ministries concerned. The Ministries have been asked to give their suggestions and comments. That is also at the active consideration. Let me assure this House that it is our intention to help the more backward States of India, and the Report is under active consideration. ...(*Interruptions*)